

Tuesday, 06 July 2021

LG rolls out Sustainable Development Fellowship

Excelsior Correspondent

SRINAGAR, July 5: With the aim of transforming the overall delivery structure of government programmes and making it more efficient, transparent, and robust, Lieutenant Governor, Manoj Sinha today rolled out the "Lieutenant Governor's Sustainable Development Fellowship (LGSDF)" for the engineering, management and other graduates of the Union Territory of J&K.

The programme, which shall be funded by the J&K Government and implemented in collaboration with IIT, Jammu, will focus on providing immediate catalytic support to improve government service delivery, removing gaps in policy implementation, and generating valuable insights for policymakers and implementing agencies.

LGSDF is providing a unique and exciting opportunity for young professionals from Premier Institutes of UT to



work towards promoting outreach, transparency, efficiency, and improving delivery of various Government Programmes, besides providing a fulfilling experience to the scholars through extensive work in the field followed by use of analytical tools/brainstorming to come

up with solutions under the guidance of IIT Jammu task force.

The objective of the programme is to provide an institutional platform for research related to enhancing delivery of Government Programmes for the graduates from Premier Institutes like IIT Jammu, IIM Jammu, NIT Srinagar, and other institutes who wish to pursue a career in development sector and have an attitude of "giving back" to the society.

Under the programme, every year 10 scholars/graduates from IIT Jammu, IIM Jammu, NIT Srinagar, and other National Institutes shall be selected, who would have requisite work experience and have qualified GATE, MAT, NET examinations.

Initially, the tenure of fellowship will be for 2 years, which shall be further extendable by 3 years. The rate of fel-

lowship shall be Rs. 60,000/- per month. The field travel and other incidentals will be reimbursed as per the adopted policy.

The Programme shall be monitored by the three-member committee consisting of the Chief Secretary, Principal Secretary to the Lt Governor, and Director, IIT Jammu. The deliverables and accountability of the projects shall be clearly defined and evolved. The committee shall identify specific departmental projects and delivery targets for each specified area for the scholars under the scheme.

The applications shall be invited through online mode once a year through advertisement in leading Newspapers and Employment News from the candidates fulfilling the eligibility conditions under the scheme.

Tuesday, 06 July 2021

LG rolls out Lieutenant Governor's Sustainable Development Fellowship for Engineering, Management, other Graduates of J&K



■ STATE TIMES NEWS

SRINAGAR: With the aim of transforming the overall delivery structure of government programmes and making it more efficient, transparent, and robust, Lieutenant Governor, Manoj Sinha on Monday rolled out the "Lieutenant Governor's Sustainable Development Fellowship (LGSDF)" for the engineering, management and other graduates of the Union Territory of J&K.

The programme, which shall be funded by the J&K Government and implement-

- ▶▶ Programme to provide an institutional platform for research related to enhancing delivery of Government welfare schemes for the graduates from Premier Institutes who wish to pursue a career in development sector
- ▶▶ Aim is to provide catalytic support to improve government service delivery, remove gaps in policy implementation & generating valuable insights for policymakers & implementing agencies: LG
- ▶▶ Every year 10 scholars/graduates from IIT Jammu, IIM Jammu, NIT Srinagar, and other National Institutes to be selected
- ▶▶ Each selected graduate to get a fellowship of Rs. 60,000 per month along with field travel allowance and other incidentals

ed in collaboration with IIT, Jammu, will focus on providing immediate catalytic support to improve government service delivery, removing gaps in policy implementation, and generating valuable insights for policymakers and implementing agencies.

LGSDF is providing a unique and exciting opportunity for young professionals from Premier Institutes of

UT to work towards promoting outreach, transparency, efficiency, and improving delivery of various Government Programmes, besides providing a fulfilling experience to the scholars through extensive work in the field followed by use of analytical tools/brainstorming to come up with solutions under the guidance of IIT Jammu task force.

The objective of the programme is to provide an institutional platform for research related to enhancing delivery of Government Programmes for the graduates from Premier Institutes like IIT Jammu, IIM Jammu, NIT Srinagar, and other institutes who wish to pursue a career in development sector and have an attitude of "giving back" to the society.

Under the programme, every year 10 scholars/graduates from IIT Jammu, IIM Jammu, NIT Srinagar, and other National Institutes shall be selected, who would have requisite work experience and have qualified GATE, MAT, NET examinations.

Initially, the tenure of fellowship will be for 2 years, which shall be further extendable by 3 years. The rate of fellowship shall be Rs. 60,000/- per month. The field travel and other

■ CONTD ON PAGE 9

LG rolls out...

incidentals will be reimbursed as per the adopted policy.

The Programme shall be monitored by the three-member committee consisting of the Chief Secretary, Principal Secretary to the Lt Governor, and Director, IIT Jammu. The deliverables and accountability of the projects shall be clearly defined and evolved. The committee shall identify specific departmental projects and delivery targets for each specified area for the scholars under the scheme. The applications shall be invited through online mode once a year through advertisement in Leading Newspapers and Employment News from the candidates fulfilling the eligibility conditions under the scheme.

आईआईटी-आईआईएम के युवाओं को मिलेगी फेलोशिप

सरकार ने शुरु की योजना, हर साल एलजी फेलोशिप योजना के तहत होगा चयन, 60 हजार रुपये प्रति माह मिलेगा

अमर उजाला ब्यूरो

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के ग्रेजुएट को सरकार स्कॉलरशिप देगी। एलजी मनोज सिन्हा ने सोमवार को इसका एलान किया। उप राज्यपाल सतत विकास फेलोशिप (एलजी फेलोशिप) के तहत हर साल 10 युवाओं का चयन होगा। इन्हें प्रति माह 60 हजार स्कॉलरशिप मिलेगी।

सरकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाने व पारदर्शिता के साथ इनकी आम लोगों तक पहुंच बनाने के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है। जम्मू-कश्मीर सरकार इस योजना को फंड प्रदान करेगी। आईआईटी जम्मू के सहयोग से लागू होने वाली योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं के निष्पादन में सुधार करना, नीति क्रियान्वयन के अंतर को दूर करना और नीति निर्माताओं-कार्यदायी संस्थाओं के लिए बहुमूल्य सुझाव देना होगा। शोध आधारित इस योजना के तहत चयनित स्कॉलर के पास अनुभव होने के साथ साथ गेट, मैट, नेट परीक्षा पास योग्यता होनी चाहिए। फेलोशिप की अवधि दो साल की होगी, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम की निगरानी मुख्य सचिव, उप राज्यपाल के प्रमुख



गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन के दौरान एलजी मनोज सिन्हा। अमर उजाला

युवाओं के लिए बजट में 513 करोड़ का प्रावधान

श्रीनगर। एलजी ने कहा कि युवाओं के लिए इस साल बजट में 513 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 करोड़ रुपये अधिक है। सुरेश रैना क्रिकेट एकेडमी युवाओं को क्रिकेट के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रही है। दस जिलों में फुटबाल कार्यक्रम चल रहे हैं जहां 750 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस साल 11 टूर्नामेंट कराए जाएंगे। 3405 मैच में डेढ़ लाख

सचिव और आईआईटी जम्मू के निदेशक की तीन सदस्यीय समिति करेगी। समिति विभागवार प्रोजेक्ट को

खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। कहा कि पीएमडीपी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 करोड़ रुपये खेल ढांचे के विकास के लिए स्वीकृत किए थे। इनमें से 20 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 11 जल्द पूरे होने वाले हैं। जेकेआईडीएफसी के तहत 134 खेल ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट को लिया गया था। इनमें से 93 पूरा हो गया है, जबकि 32 अगले महीने तक पूरा हो जाएंगे। ब्यूरो

चिह्नित करेगी। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन साल में एक बार आमंत्रित किए जाएंगे।

एकेडमी में पहले बैच में प्रदेश के 50 गोल्फर लेंगे प्रशिक्षण

श्रीनगर। श्रीनगर में गोल्फ एकेडमी में पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। अगले 15 दिन तक यहां प्रशिक्षण चलेगा। पहले बैच में सरकारी स्कूलों के 50 उभरते गोल्फर (25 लड़के व 25 लड़कियों) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देशभर के चुनिंदा कोच प्रशिक्षण के लिए आएंगे जिसमें भारतीय टीम के कप्तान अमनदीप भी शामिल हैं। उद्घाटन के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में खेल संस्कृति विकसित करने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रतिभाओं को प्लेटफार्म मिल सके। इसके लिए सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कहा कि इस साल 17 लाख बच्चों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। खेल को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है। यह तय किया गया है कि इस साल राष्ट्रीय स्तर की 17 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सभी 4290 पंचायतों को दो-तीन खेल गतिविधियों से जोड़ा गया है। जिन पंचायतों में खेल मैदान नहीं हैं उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। एलजी गोल्फ ट्रेनिंग हैडबुक लांच करने के साथ ही खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स यूनिफार्म भी प्रदान की गई। ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर में युवाओं पर केंद्रित योजनाओं को प्राथमिकता : एलजी

अमर उजाला ब्यूरो

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के युवाओं का भविष्य बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अभी तक 150 से अधिक पहल की हैं। युवाओं पर केंद्रित योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को यह बात कही। एलजी वर्चुअल मोड के माध्यम से आईआईएम रोहतक के पीजी कार्यक्रम के 12वें इंडक्शन बैच के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को नवाचार से जोड़कर देश का भविष्य संवरेगा। समय आ गया है कि युवाओं को अपने आप में बदलाव लाना होगा, ताकि नवाचार और क्रिएटिविटी से नई ऊंचाइयां छू सकें। छात्रों के समक्ष आ रही चुनौतियों को अवसर में बदलना होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। कहा - जम्मू-कश्मीर मेरे दिल के करीब है। यहां पर बदलाव एक कदम हजारों लोगों की आकांक्षाओं को



आईआईएम रोहतक के 12वें बैच के इंडक्शन का मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन

पूरा करेगा। 3500 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना के साथ-साथ भूमि कानूनों में सुधार, सेब की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई उद्योग नीति देश की बेहतर नीति और औद्योगिक नीतियों में से एक है। इसके तहत 20 हजार करोड़ का निवेश आकर्षित कर रोजगार के 5 लाख अवसर सृजित किए जाएंगे। एलजी ने आईआईएम अहमदाबाद के मेधावी छात्र भारतेंदु वर्मा का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ काम करते हुए छह माह में हासिल जैसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने में सफलता हासिल की है।

LG rolls out “Lieutenant Governor's Sustainable Development Fellowship (LGSDF)” for Engineering, Management & other Graduates of J&K

Srinagar, July 5:(KNS) With the aim of transforming the overall delivery structure of government programmes and making it more efficient, transparent, and robust, Lieutenant Governor, Manoj Sinha today rolled out the “**Lieutenant Governor's Sustainable Development Fellowship (LGSDF)**” for the engineering, management and other graduates of the Union Territory of J&K.

The programme, which shall be funded by the J&K Government and implemented in collaboration with IIT, Jammu, will focus on providing immediate catalytic support to improve government service delivery, removing gaps in policy implementation, and generating valuable insights for policymakers and implementing agencies.

LGSDF is providing a unique and exciting opportunity for young professionals from Premier Institutes of UT to work towards promoting outreach, transparency, efficiency, and improving delivery of various Government Programmes, besides providing a fulfilling experience to the scholars through extensive work in the field followed by use of analytical tools/brainstorming to come up with solutions under the guidance of IIT Jammu task force.

The objective of the programme is to provide an institutional platform for research related to enhancing delivery of Government Programmes for the graduates from Premier Institutes like IIT Jammu, IIM Jammu, NIT Srinagar, and other institutes who wish to pursue a career in development sector and have an attitude of "giving back" to the society.

Under the programme, every year 10 scholars/graduates from IIT Jammu, IIM Jammu, NIT Srinagar, and other National Institutes shall be selected, who would have requisite work experience and have qualified GATE, MAT, NET examinations. Initially, the tenure of fellowship will be for 2 years, which shall be further extendable by 3 years. The rate of fellowship shall be Rs. 60,000/- per month. The field travel and other incidentals will be reimbursed as per the adopted policy.

The Programme shall be monitored by the three-member committee consisting of the Chief Secretary, Principal Secretary to the Lt Governor, and Director, IIT Jammu. The deliverables and accountability of the projects shall be clearly defined and evolved. The committee shall identify specific departmental projects and delivery targets for

The applications shall be invited through online mode once a year through advertisement in Leading Newspapers and Employment News from the candidates fulfilling the eligibility conditions under the scheme.